

पीठ दर्द और मानसिक तनाव की बढ़ी समस्या

■ आकर्ष धनुरासन एक अचूक और प्रभावी योगासन

■ पेट के अंगों पर पड़ने वाले दबाव से जाचन किया सुधार

नई दिल्ली, (एजेंसियां)। आधुनिक जीवनशैली में पीठ दर्द, कंधों की जकड़न और मानसिक तनाव एक आम समस्या बन गई है। ऐसे में आकर्ष धनुरासन एक अचूक और प्रभावी योगासन की तरह काम करता है। यह आसन न केवल शारीरिक लचीलापन और शक्ति को बढ़ाता है, बल्कि साधक में एकाग्रता और मानसिक दृढ़ता का संचार भी करता है।

संस्कृत के तीन शब्दों 'आ' (तक), 'कर्ण' (कान), और 'धनुष' (कमान) से मिलकर बने इस आसन का शाब्दिक अर्थ है 'कान तक धनुष को खींचना'। यह आसन मुख्य रूप से जांघों, कूल्हों और कंधों के लचीलेपन को बढ़ाने और एकाग्रता में सुधार करने में मदद करता है।

आयुष मंत्रालय ने इस आसन को शरीर में शक्ति, संतुलन और लचीलापन लाने वाला प्रभावी योगाभ्यास बताया है। उनके अनुसार, यह मुद्रा साधक को धनुष की तरह आकार देती है, जिससे एकाग्रता बढ़ती है और

रौब, पीठ तथा पैरों को मांसपेशियां मजबूत होती हैं।

आकर्ष धनुरासन के नियमित अभ्यास से पीठ, कंधे और छतों की मांसपेशियां मजबूत होती हैं। रौब की हड्डी लचीली और स्वस्थ बनी रहती है, जिससे पीठ दर्द में काफी राहत मिलती है। पेट के अंगों पर पड़ने वाले दबाव से जाचन क्रिया सुधरती है और कब्ज जैसी समस्याएं दूर होती हैं। पैरों, जांघों और कूल्हों की मांसपेशियां खिंचती हैं। यह आसन संतुलन और एकाग्रता को भी

बेहतर बनाता है। मानसिक स्तर पर यह मुद्रा आत्मविश्वास की भावना को मजबूत करती है।

एक्सपर्ट के अनुसार, आकर्ष धनुरासन शरीर और मन दोनों में संतुलन स्थापित करने वाला एक शक्तिशाली

मुंह की अच्छी सेहत के लिए 'गंडूषा' का अभ्यास

नई दिल्ली। आयुष मंत्रालय की ओर से मुंह की सेहत को अच्छा रखने के लिए पारंपरिक उपचार पद्धति गंडूषा की प्रैक्टिस को लेकर जानकारी सझा की गई है। मोरार जींदिया एंसेलॉजी 'एक्स' पर एक पोस्ट में आयुष मंत्रालय ने लिखा कि अपने दिन की शुरुआत गंडूषा से करें, जो एक पुरानी आयुर्वेदिक ओरल केयर प्रैक्टिस है और मुंह की पूरी सेहत में मदद करती है। 'एक हेलोय दिनबर्न के हिस्से के तौर पर यह पारंपरिक घाउप रिस न्यादा प्यास को रोकने, स्वाद समझने की क्षमता को बेहतर बनाने और पैचुरली मुँह को सफाई बनाए रखने में मदद करता है। इस आसन रोजाना की आदत को अपनाएं और आयुर्वेद के फायदों का अनुभव करें। एक बार में एक घण्टा देने वाली आदत अपनाएं।' अर्थविकासन (इफ व्हेल पोड) रौब की हड्डी की फ्लैक्सिबिलिटी को बेहतर बनाने, पीठ की मांसपेशियों को मजबूत करने और बेसल पोस्चर में मदद करता है। रेगुलर प्रैक्टिस से, सही ग्राइंडिंग में सही तरीके से करने पर, सर्वांकलत स्पोन्डिलोसिस के मैनेजमेंट में भी मदद मिल सकती है। जोते दिन आयुष मंत्रालय ने नारी बनने से लेकर मां बनने तक एक कैलेंडर लाइफस्टाइल के बारे में पोस्ट शेयर किया था। मंत्रालय की ओर से लिखा गया था, नारी बनने से लेकर मां बनने तक एक कैलेंडर लाइफस्टाइल अपनाता मां और बनने वाली की सेहत के लिए बहुत जरूरी है। पूरा आसन, अच्छी साफ-सफाई, रेगुलर फिजिकल एक्टिविटी और समय पर एंटीनेटल चेक-अप एक हेलोय डेनैसी और बच्चे के जन्म के अन्धे अनुभव में मदद करते हैं।

योगासन है, जो योग साधकों के लिए विशेष रूप से लाभकारी सिद्ध होता है, हालांकि शुरुआत में शैलों को किसी योग प्रशिक्षक की देखरेख में ही यह आसन करना चाहिए। आसन के अभ्यास के दौरान शरीर पर किसी तरह का दबाव नहीं

डालना चाहिए। अगर आपकी पीठ (स्माइन) या गर्दन में कोई गंभीर विकार या चोट है, तो इस आसन को करने से बचें। अभ्यास के दौरान किसी विशेषज्ञ की निगरानी में करें और शरीर पर जबरदस्ती दबाव न डालें।

72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार विजेताओं की घोषणा

मुंबई, (एजेंसियां)। 72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के विजेताओं की घोषणा शनिवार को राष्ट्रीय मीडिया केंद्र में की गई। बॉलीवुड अभिनेता कार्तिक आर्यन और मलयालम सिनेमा के दिग्गज मम्तूजी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

मम्तूजी को फिल्म 'ब्रह्मपुत्र' के

■ कार्तिक आर्यन व मम्तूजी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, 'आर्टिकल 370' के लिए यागी सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री घोषित

खोलने' को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार मिला। निर्देशक सुकुमार को 'पुष्पा 2' के लिए सर्वश्रेष्ठ पटकथा का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। संगीतकार शश्वत साधने को 'आर्टिकल 370' के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन का पुरस्कार मिला। सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन डिजाइन का पुरस्कार 'कलिक 2898 ईस्वी' को मिला, जबकि 'स्त्री 2' को सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार दिया गया।

72वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2024 में भारतीय सिनेमा में उत्कृष्टता को मान्यता देते हैं। इन पुरस्कारों की घोषणा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा की गई। पुरस्कारों का मूल्यांकन 11 सदस्यीय केंद्रीय जुरी द्वारा किया गया, जिसकी अध्यक्षता प्रख्यात मलयालम फिल्म निर्माता जयराम ने की। जयराम ने देश भर से प्राप्त प्रविष्टियों को समीक्षा करने के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया का संचालन किया।

इस कार्यक्रम का आयोजन भारतीय राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एनएफडीसी) द्वारा किया जाता है और इसमें एक सुव्यवस्थित निर्वाचक मंडल होता है। इन पुरस्कारों का उद्देश्य सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर, औपचारिक प्रस्तुति को बनाए रखते हुए भारतीय सिनेमा की कलात्मक और तकनीकी उपलब्धियों का सम्मान करना है।

दोनों टीमों के कोचों की रणनीति से तय होगा नतीजा : अमिताभ बच्चन

मुंबई, (एजेंसियां)। फीफ वर्ल्ड कप 2026 का फाइनल मुकाबला क्रिकेटिंग चैंपियन अर्जेंटीना और स्पेन के बीच खेला जावे है। इस बीच विश्व कप के छितावी मुकबले को लेकर बॉलीवुड के दिग्गज अभिनेता अमिताभ बच्चन का कहना है कि टूर्नामेंट में बचे सभी खिलाड़ी सुपरस्टार हैं, लेकिन असली विजेता का फैसला कोच की रणनीति और समझदारी से होगा। अमिताभ ने अपने ज़ांग पर इंग्लैंड के खिलाफ अर्जेंटीना के साहसी सविट्ट्युशुन (खिलाड़ी बदलने) पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने इस जोखिम भी, लेकिन निर्बाधक कदम की तारीफ करते हुए इसे निजर गेम मैनेजमेंट का सबूत बताया। विश्व वी ने अपने ज़ांग पर लिखा कि जब आप चैंपियनशिप के अखिरी पड़ाव पर पहुंचते हैं और

आपस में मुकाबला करने के लिए सिर्फ 4 टीमों बची होती हैं तो भीव्यवधानी करना मुश्किल होता है। भीव्यवधानियों आपके पसंदीदा के प्रति आपके प्यार और लगाव पर आधारित होती हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इस स्टेज पर हम 44 खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं। सेमीफाइनल से फाइनल तक, हर टीम में 11 खिलाड़ी और मुकाबले के इस स्टेज पर हर खिलाड़ी एक सुपरस्टार है। उन्होंने कहा कि आप एक खिलाड़ी के तौर पर उनकी हौसला नहीं बदल सकते, लेकिन तबवरी में अभिनेत्री इस बात को है कि उन्हें कैसे मैनेज किया जाए और वहीं कोच या मैनेजर की भूमिका आती है। इसी वजह से रीक्वियर को होने वाला फाइनल स्पेनिस कोच और अर्जेंटीना के कोच के बीच मुकाबला होगा।

फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने शहर के पहले लंग फेलियर क्लीनिक का उद्घाटन किया

मानेसर (एजेंसियां)। फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर ने शहर के पहले लंग फेलियर क्लीनिक का उद्घाटन किया जहां एडवॉंस और एंड-स्टेज लंग डिजीज (फेफड़ों के गंभीर एवं अंतिम चरण के रोगों) से पीड़ित मरीजों के उपचार एवं देखभाल की व्यापक रूप से सुविधाएं मुलत करायी गई हैं। इस क्षेत्र में अपनी तरह के ऐसे गिने-चुने स्पेशलाइज्ड क्लीनिकों में से एक, लंग फेलियर क्लीनिक में लंग ट्रांसप्लान्टेशन सेवाओं समेत एडवॉंस लंग फेलियर के प्रबंधन की व्यापक सेवाएं उपलब्ध करायी गई हैं। क्लीनिक का संचालन प्रत्येक बुधवार तथा शुक्रवार को दोपहर 2.00 बजे से अपराह्न 4.00 बजे के दौरान फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर में किया

जाएगा जहां इसकी कमान डॉ गोविनी कलामुब्रमणि, डायरेक्टर - लंग ट्रांसप्लान्ट एंड एडवॉंस लंग फेलियर, एलैन्डरलस हॉस्पिटल, चेन्नई (फोर्टिस नेटवर्क के अंतर्गत कार्यरत अस्पताल) तथा डॉ कर्ण मेहरा, सीनियर कंसल्टेंट एंड यूनिट हेड - एडवॉंस लंग फेलियर एंड ट्रांसप्लान्ट पल्मोनोलॉजी, फोर्टिस हॉस्पिटल मानेसर संभालेंगे।

क्लीनिक में एडवॉंस लंग फेलियर से

प्रस्त मरीजों को उनके रोग के विस्तृत मूल्यांकन, मेडिकल थैरेपी ऑप्टिमाइजेशन, तथा लंग ट्रांसप्लान्टेशन के लिए उपयुक्तता संबंधी परामर्श उपलब्ध कराया जाएगा। उपयुक्त पाए जाने वाले मरीजों के लिए प्री-ट्रांसप्लान्ट काउंसलिंग, विस्तृत क्लीनिकल जांच और पोस्ट-ट्रांसप्लान्ट फॉलो-अप की सेवाएं ट्रांसप्लान्ट विशेषज्ञों के सहयोग से सुनिश्चित की जाएंगी। इसके अलावा, मरीजों के लिए एडवॉंस पल्मोनोरी फंक्शन टेस्टिंग, ब्रॉन्कोस्कोपी तथा इंटरवेंशनल एलमोनोलॉजी प्रक्रियाओं, एलमोनोरी रीहैबिलिटेशन प्रोग्रामों, पोषण संबंधी परामर्श, नॉड के मूल्यांकन, नॉन-इन्वैसिव वेंटिलेशन सपोर्ट और व्यक्तिगत मरीज शिक्षा की सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।

एशियाई शेरों को लेकर अध्ययन में खुलासा

तटीय एशियाई शेर ज्यादातर जंगली शिकार पर निर्भर

मांथीनगर, (एजेंसियां)। गुजरात के तट पर रहने वाले एशियाई शेरों को लेकर एक स्टडी सामने आई है। नई सांख्यिकीय स्टडी में पाया गया कि गुजरात के तट पर रहने वाले एशियाई शेर पालतु जानवरों के बजाय मुख्य रूप से जंगली शिकार पर निर्भर रहते हैं। इस स्टडी के बाद से यह पुरानी सोच बदल गई है कि यह प्रजाति भवैशियों की उत्ताशा में गिर के जंगलों से आगे बढ़ी।

पोर-रिप्यूड इंटरनेशनल जर्नल 'कंजर्वेशन' में छपी रिपोर्ट में पाया गया कि कोस्टल एशियाई शेरों द्वारा खाए जाने वाले बायोमास का लगभग 70 प्रतिशत जंगली शिकार से आता है, जो गिर प्रोटेक्टेड एरिया के बाहर इस प्रजाति के बड़े रहने की जगह की पर्यावरणीय व्यवस्थाओं को दिखाता है। यह नतीजा तब सामने आया है जब 2025 में किए गए 16वें लायन एंथुपेलेशन एंथिमेसन के अनुसार, राज्य में एशियाई शेरों की आबादी 891 तक पहुंच गई है।

सौराष्ट्र, गुजरात, भारत के कोस्टल इकोसिस्टम में एशियाई शेरों का डाइटी पटर्न टाइटल वाली इस स्टडी

■ नीलगाय और जंगली सुअरों का शेर ज्यादातर कर रहे हैं शिकार

■ तटीय जंगलों पर 100 से ज्यादा एशियाई शेरों के होने का अंदाजा



के लेखक मोहन राम, आमाचना सझ, किवानंद श्रीवासव, कुलज वदार्, रोहित चौधरी और लखर इला हैं। रिपोर्ट में मार्च और अप्रैल 2024 के दौरान जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और पोरबंदर के तटीय जिलों से इकट्ठ किए गए 160 शेरों के मल के सैंपल का एनालिसिस किया। जूनागढ़ सर्कल के कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट्स और स्टडी के लेखकों में से एक मोहन राम ने कहा कि हमारी स्टडी में मार्च और अप्रैल 2024 के दौरान जूनागढ़, गिर सोमनाथ, अमरेली, भावनगर और पोरबंदर के तटीय

गुं, जो खाए गए कुल बायोमास का आधे से ज्यादा (51) प्रतिशत) हिस्सा थी। जंगली सुअर दूसरा सबसे बड़ा जंगली शिकार थे, जबकि गवेरी सबसे बड़ा परेलु शिकार थे। रिपोर्ट में कहा कि नतीजे उनकी असली सोच से उलट थे कि इसानी आबादी वाले तटीय इलाकों में रहने वाले शेर जंगली शिकार की कम नीजुदगी के कारण जानवरों पर ज्यादा निर्भर रहेंगे। स्टडी का नतीजा यह निकला कि गुजरात के तटीय इलाकों में नीलगाय और जंगली सुअरों की अच्छी आबादी होने के कारण शेर ज्यादातर शिकार कर रहे हैं, जिससे जानवरों पर दबाव कम हो सकता है और ईमान-शेर के बीच टकराव को कम करने में मदद मिल सकती है। स्टडी के मुताबिक, गुजरात का तटीय इकोसिस्टम अब दक्षिण-पश्चिमी तट, दक्षिण-पूर्वी तट और भावनगर तट पर एशियाई शेरों की तीन जरूरी सैटलाइट आबादी को संभाले करता है। इन तटीय आबादों पर कुल मिलाकर 100 से ज्यादा एशियाई शेरों के होने का अंदाजा है, जो गिर के जंगलों से आगे इस प्रजाति के लगातार फैलने को दिखाता है।

मुंबई, (एजेंसियां)। ग्लोबल आइकन अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा के जन्मदिन के मौके पर निर्देशक एस.एस. राजामौली समेत फिल्म वारापक्षी की टीम ने अभिनेत्री का पहला लुक जारी किया, जिसमें उन्हें फिल्म में उनके किरदार मंदाकिनी के रूप में दिखाया गया है। मशहूर निर्देशक एस.एस. राजामौली ने इंस्टाग्राम पर प्रियंका की दो तस्वीरें शेयर कीं। पहली तस्वीर में अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा इंटिम अवतार में नजर आ रही हैं। कलते रंग की कॉमिट-स्टाइल आउटफिट में अभिनेत्री लीखे एक्सप्रेशन दे रही हैं। गर्म, एक्बर लवट वाले बैकग्राउंड के सामने यह

तस्वीर मंदाकिनी के किरदार के पावरफुल साइड की ओर इशारा करती है।

बाई, दूसरी तस्वीर में प्रियंका बॉफिकर और मस्तमौली अंदाज में हैं। ब्लाइट जॉय टीप, ब्लैक काली पैट और कंधों पर केब जैकेट पहने एक्ट्रेस हाथ फैलाकर हवा में उछलती हुई दिख रही हैं। अभिनेत्री की

मुस्कान, उनके कैरेक्टर का जिज्ञा राजामौली ने अपने कैप्शन में किया। उन्होंने लिखा कि जब वह मुकुंरती हैं तो बहुत प्यारी और मुकून देने वाली लगती हैं और जब नहीं मुकुंरती, तो उसके गुस्से और तेज अंग जैसे लगते हैं। इसी के साथ ही प्रियंका चोपड़ा के सह-कलाकार महेश बाबू और पूर्वजीवन मुकुंरान ने भी इंस्टाग्राम पर अभिनेत्री का पहला लुक शेयर किया। 'धनन-1' प्रियंका चोपड़ा आगामी फिल्म वारापक्षी के साथ फ्लॉप सिनेमा में बापक्षी कर रही हैं। इसमें उनके साथ महेश बाबू 'स्ट' नाम का एक कैरेक्टर निभा रहे हैं।

दर्द को गीतों में पिरोकर अमर हो गए शब्दों के जादूगर गोपालदास 'नीरज'

नई दिल्ली, (एजेंसियां)। 4 जनवरी 1925 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के पुरावली गांव में जन्मे गोपालदास सम्सेन उर्फ 'नीरज' का शुरुआती जीवन लंगहली में गुजरा। मात्र 6 वर्ष की उम्र में पिता का साथी मिर से उठ जाने के कारण उन पर परिवार की जिम्मेदारी आ गई। घर का चुल्हा जलाने के लिए उन्होंने पेट की छाछी गंगा नदी में गोता लगाकर ब्रह्मलुओं द्वारा फेंके गए सिक्के बटोरें, गलियों में घूम-घूमकर बीड़ी-सिगरेट बेची और यहाँ तक कि दोचारों पर फिल्मों के पोस्टर भी निपकाए। उन्होंने शाब्द ही कभी सोचा होगा कि एक दिन उनकी फिल्मों पीटस्टों पर उनका नाम ज़ोर देर के सबसे बड़े गीतकार मुहुरे अक्षरों में चमकेगा। तमाम

के बचपन से और हम खड़े-खड़े बाहर देखते रहे, कजरवां गुजर गया गुवार देखते रहे।

व्यक्तिगत दुख की सार्वभौमिक दर्शन में बदलने वाला यह गीत जब रेडियो पर प्रसारित हुआ, तो इसने गोपालदास नीरज को रातोंरात पूरे देश का चर्चा बना दिया। अध्यापन के क्षेत्र में कदम रखते हुए उन्होंने मेरठ कॉलेज में पढ़या, लेकिन प्रशासन द्वारा लगाए गए 'रोमंस' और कक्षाएं न लेने के छुटे आरोपों से आहत होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके पश्चात 1956 में वे अलीगढ़ के धर्म

समाज कॉलेज में प्रोफेसर बन गए और अलीगढ़ ही उनका स्थायी ठिकाना बन गया। कवि समीरलनों में उनकी बढ़ती लोकप्रियता ने माधवगरी का ध्यान खींचा और निर्देशक आर

जंदा उन्हें बम्बई ले आए। फिल्मों में उनके आगमन ने फिल्मी गीतों को एक नई साहित्यिक गरिमा प्रदान की। यह एक ऐसा दौर था जब उनके रचित गीत सीधे श्रोताओं की आत्मा में उतर जाते थे। प्रसिद्ध फिल्मों गीतों में नई उमर की नई फसल (1965) का कजरवां गुजर गया रोशन के संगीत और मोहम्मद रफी की आवाज में है। कन्यादान (1968) का 'लिखे जो ख़ात तुझे' श्रवक-जवकिशन और रफी का गीत है। उनके इस अद्वितीय ध्वाइ और काव्यरमक योगदान के लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म श्री और 2007 में पद्मभूषण से सम्मानित किया। उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें 1994 में यश भारती पुरस्कार से नवाजा। 19 जुलाई, 2018 को दिल्ली के एम्स अस्पताल में इस महान गीत-ख़ुश ने अपनी अंतिम सांस ली। उन्होंने अपना पार्थिव शरीर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की चिकित्सक शोध के लिए दान कर दिया था।

संपादक की कलम से

बेटियों की सुरक्षा का संकट

तकनीक के विकास के साथ-साथ मानवीय मूल्य और संवेदनाएं कमजोर होती जा रही हैं। इससे सामाजिक संबंधों के समक्ष विश्वास का संकट पैदा हो गया है। मानवीय मूल्य वे मूलभूत नैतिक मानक एवं सिद्धांत होते हैं, जो हमारे आचरण को दिशा देते हैं, जबकि संवेदनाएं दूसरों के सुख-दुख को महसूस करने की क्षमता हैं। ये दोनों मिलकर व्यक्ति को सामाजिक रूप से जिम्मेदार इंसान बनाते हैं। मगर जब मनुष्य की सोच से ये दोनों तत्त्व गायब हो जाएं, तो सभ्य समाज का आधार भी निर्बल हो जाता है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा और यौन दुर्व्यवहार की बढ़ती घटनाएं भी इसी का नतीजा है। भर्त्सु हिंसा को तो समाज में कई बार सामान्य घटना के रूप में देखा जाता है। यही वजह है कि सख्त कानून होने के बावजूद इस तरह की घटनाओं पर अंकुश नहीं लग पा रहा है।

कई बार यौन दुर्व्यवहार के मामलों में दोषी को न्याय के कठघरे में लाने के बजाय समाज पीड़िता के पहनावे, रहन-सहन या आचरण को दोषी ठहराने लगता है। इससे ऐसा लगता है कि पितृसत्तात्मक समाज अपराधी को बचाने और महिलाओं को प्रताड़ित करने का समर्थन कर रहा है। स्त्रीवादी कैथरीन मैककिनन का मानना है कि बलात्कार पुरुष शक्ति और प्रभुत्व का एक चरम रूप है। इसके जरिए महिलाओं को डराकर और नियंत्रित करके रखा जाता है।

हाल की कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो पता चलता है कि अपराधियों की मानसिकता किस हद तक विकृत होती जा रही है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक बच्ची का अपहरण कर पांच दिन तक बत्तीस लोगों ने उससे बलात्कार किया। पश्चिम बंगाल के बुरुईपुरा में एक बच्ची से सामूहिक बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई।

उत्तर प्रदेश के बरेली में एक लड़की और हरदोई में एक बच्ची से बलात्कार के बाद हत्या कर दी गई। सवाल है कि क्या इन बच्चियों के साथ हुई यौन हिंसा के लिए भी उनके कपड़ों, व्यवहार और चाल-चलन को दोषी ठहराया जाएगा? यह सच है कि पहले की तुलना में महिलाओं को अब अनेक अधिकार प्राप्त हैं, लेकिन इन सबके बावजूद उन्हें अपने अस्तित्व और अस्मिता की सुरक्षा का अधिकार अभी तक नहीं मिल पाया है। आए दिन सड़कों, ट्रेनों, बसों, घरों, खेतों और दफ्तरो में लड़कियां एवं महिलाओं को वह सब झेलना पड़ता है, जो अनैतिक और गैर-कानूनी है। फिर भी यह सब खुलेआम हो रहा है, जैसे उसे सामाजिक वैधता प्राप्त हो। सरकार की ओर से नए कानून बनाए जाते हैं या पहले से बने कानूनों में संशोधन किया जाता है, लेकिन सवाल यह है कि इन्हें सख्ती से लागू करने की जिम्मेदारी किसकी है? जांच प्रक्रिया इतनी धीमी और लापरवाही भरी होती है कि कई मामलों में पीड़िता को न्याय मिल ही नहीं पाता है और अगर कहीं न्याय मिलता भी है, तो उसके लिए वर्षों इंतजार करना पड़ता है।

महिलाओं की सुरक्षा पर केंद्रित कार्यशालाओं और बौद्धिक चर्चाओं में कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह दी जाती रही हैं। जैसे- गाड़ी में बैठने से पहले पिछली सीट पर देख लें, मोबाइल फोन में हेल्पलाइन नंबर रखें, रात में बाहर न निकलें, सोते समय सभी खिड़कियां बंद कर लें, अनजान लोगों से खाने-पीने की कोई वस्तु न लें, मिर्च स्प्रे साथ रखें, काम से घर जाते समय अपना रास्ता बदलते रहें और कोई संदेह होने पर तत्काल पुलिस को सूचित करें। सवाल है कि ये सावधानियां बच्चों और किशोरियों को कैसे सिखाई जाएं? और क्या संपावित समस्याओं का हल केवल यही है कि लड़कियां एवं महिलाओं को ही सावधान रहना होगा। क्या वास्तव में इन सब सावधानियों से यौन हिंसा की घटनाएं रुक जाएंगी? देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि किसी भी देश की स्थिति वहां की महिलाओं की स्थिति को देखकर ज्ञात की जा सकती है। यदि इस तर्क को सही माना जाए, तो फिर इस दावे के क्या मायने रह जाते हैं कि भारत दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं की पंक्ति में खड़ा है। जिस देश की आधी आबादी को यौन शोषण, घरेलू हिंसा, तेजाब हमले और दहेज के लिए हत्या जैसी अमानवीय घटनाओं का दंश झेलना पड़ रहा हो, उस देश की स्थिति क्या होगी, यह बताने की जरूरत नहीं है।

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने या महिला सशक्तीकरण का उद्घोष करने से ही अगर उनकी स्थिति में बदलाव लाया जा सकता, तो अब तक यह सब हो चुका होता। दरअसल, सवाल यहां महिला सशक्तीकरण का है ही नहीं, उन्हें मजबूत या सशक्त बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वे पहले से ही मजबूत हैं। जरूरत है समाज में महिलाओं की ताकत का आकलन करने के नजरिे को बदलने की। अगर पुरुष समाज महिलाओं के प्रति अपने नजरिए को बदल ले, तो समस्या अपने आप समाप्त हो जाएगी।

सवाल है कि क्या बलात्कार को सामूहिक आतंकवाद की संज्ञा दी जा सकती है? आतंकवाद में भी भय उत्पन्न करके दूसरों के व्यवहार पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है और बलात्कार में भी महिलाओं के व्यवहार को नियंत्रित कर उन पर अपना आधिपत्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। पहले के समय में बलात्कार की अधिकतर घटनाओं के लिए अपरिचित या अजनबी दोषी होता था, लेकिन अब परिवार, दोस्त और रिश्तेदारी के दायरे में भी महिलाएं यौन उत्पीड़न की शिकार हो रही हैं। असल में महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा तभी मिलेगा, जब उन्हें पुरुषों के समान सारे अधिकार मिलेंगे। लैंगिक समानता आधारित समाज वह होता है, जहां हर कोई जैसा है, वैसा रह सके। इसलिए जरूरत इस बात की है कि देश की न्यायिक और सामाजिक व्यवस्था में आमूल-चूल बदलाव किया जाए तथा महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर स्तर पर गंभीरता से प्रयास किए जाएं।



महेन्द्र तिवारी

पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही बलूचिस्तान का प्रश्न इस्लामाबाद के लिए गले की हड्डी बना रहा है। बलूच लोगों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि वर्ष उन्नीस सौ सैंतालीस में उनके तत्कालीन राज्य कलात का पाकिस्तान में विलय उनकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध किया गया था। इसी ऐतिहासिक असंतोष ने समय के साथ एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया, जो हर गुजरते दशक के साथ अधिक उग्र और हिंसक होता गया। बलूच राष्ट्रवादियों की सबसे मुख्य शिकायत यह है कि उनके क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा केवल एक आर्थिक उपनिवेश के रूप में देखा जाता है। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, तांबे, सोने और अन्य बहुमूल्य खनिजों का अथाह भंडार है। इसके बावजूद इन विशाल संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक बहुत ही नगण्य हिस्सा स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से योजनाबद्ध तरीके से वंचित रखा गया है, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत के अभिजात्य वर्ग इन संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यह घोर आर्थिक असमानता उस गुस्से को और भड़काती है जो अंततः आम युवाओं को मुख्यधारा से काटकर विद्रोही गुटों की ओर धकेलता है।

हाल के वर्षों में बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे कई विद्रोही संगठनों ने अपनी रणनीतिक क्षमता और मारक शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि की है। पहले वर्षों में हमले केवल डिप्युट और प्रतीकात्मक होते थे, वहीं अब ये बेहद सुनियोजित और बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वर्तमान विद्रोह की एक और विशेष बात यह है कि इसकी कमान अब केवल पारंपरिक कबीलाई सरदारों के हाथों में नहीं रही है, बल्कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षित मध्यवर्गीय युवा और यहां तक कि महिलाएं भी

पाकिस्तान का सबसे बड़ा और संसाधन संपन्न प्रांत बलूचिस्तान एक बार फिर गहरी अशांति और अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक चर्चा के केंद्र में आ गया है। पिछले कुछ समय में इस क्षेत्र से छनकर आ रही खबरें, विद्रोही गुटों के दावे और पाकिस्तानी सैन्य प्रतिष्ठान की प्रतिक्रियाएं इस बात का स्पष्ट संकेत हैं कि यह विवाद अब एक नए और अधिक हिंसक चरण में प्रवेश कर चुका है। बलूच राष्ट्रवादियों द्वारा पाकिस्तानी सैन्य चौकियों पर हमलों के दावे और इसके जवाब में सेना के व्यापक अभियानों ने पूरे क्षेत्र की सुरक्षा स्थिति को बेहद नाजुक बना दिया है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस आधुनिक युग में दोनों पक्षों की ओर से सूचना और दुष्प्रचार का जो युद्ध लड़ा जा रहा है, उसने जमीनी हकीकत को समझना और भी चुनौतीपूर्ण कर दिया है। हालांकि यह विवाद केवल हालिया सैन्य झड़पों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें दशकों पुराने राजनीतिक असंतोष, आर्थिक वंचना और पहचान के संकट में गहराई तक समाहित हैं जो अब एक नासूर का रूप ले चुकी हैं।

पाकिस्तान के निर्माण के समय से ही बलूचिस्तान का प्रश्न इस्लामाबाद के लिए गले की हड्डी बना रहा है। बलूच लोगों का एक बड़ा वर्ग यह मानता है कि वर्ष उन्नीस सौ सैंतालीस में उनके तत्कालीन राज्य कलात का पाकिस्तान में विलय उनकी स्पष्ट इच्छा के विरुद्ध किया गया था। इसी ऐतिहासिक असंतोष ने समय के साथ एक मजबूत राष्ट्रवादी आंदोलन को जन्म दिया, जो हर गुजरते दशक के साथ अधिक उग्र और हिंसक होता गया। बलूच राष्ट्रवादियों की सबसे मुख्य शिकायत यह है कि उनके क्षेत्र को पाकिस्तान द्वारा केवल एक आर्थिक उपनिवेश के रूप में देखा जाता है। बलूचिस्तान प्राकृतिक गैस, तांबे, सोने और अन्य बहुमूल्य खनिजों का अथाह भंडार है। इसके बावजूद इन विशाल संसाधनों से प्राप्त होने वाले राजस्व का एक बहुत ही नगण्य हिस्सा स्थानीय विकास कार्यों पर खर्च किया जाता है। स्थानीय निवासियों को रोजगार, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से योजनाबद्ध तरीके से वंचित रखा गया है, जबकि इस्लामाबाद और पंजाब प्रांत के अभिजात्य वर्ग इन संसाधनों का भरपूर लाभ उठा रहे हैं। यह घोर आर्थिक असमानता उस गुस्से को और भड़काती है जो अंततः आम युवाओं को मुख्यधारा से काटकर विद्रोही गुटों की ओर धकेलता है।

हाल के वर्षों में बलूच लिबरेशन आर्मी जैसे कई विद्रोही संगठनों ने अपनी रणनीतिक क्षमता और मारक शक्ति में अप्रत्याशित वृद्धि की है। पहले वर्षों में हमले केवल डिप्युट और प्रतीकात्मक होते थे, वहीं अब ये बेहद सुनियोजित और बड़े पैमाने पर किए जा रहे हैं। वर्तमान विद्रोह की एक और विशेष बात यह है कि इसकी कमान अब केवल पारंपरिक कबीलाई सरदारों के हाथों में नहीं रही है, बल्कि विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले शिक्षित मध्यवर्गीय युवा और यहां तक कि महिलाएं भी

इसमें सक्रिय रूप से शामिल हो रही हैं। सैन्य ठिकानों, पुलिस चौकियों और संचार तथा यातायात के महत्वपूर्ण ढांचों पर होने वाले निरंतर हमले यह दर्शाते हैं कि विद्रोही अब सीधे तौर पर पाकिस्तानी राज्य की सत्ता और संप्रभुता को चुनौती दे रहे हैं। विद्रोही गुटों का दावा है कि उन्हें आम जनता का व्यापक समर्थन प्राप्त है और वे अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। दूसरी ओर पाकिस्तानी सेना और सरकार का रुख हमेशा की तरह बेहद कड़ा है। वे इन विद्रोहियों को केवल राज्य के दुश्मन और विदेशी ताकतों के मोहरे के रूप में चित्रित करते हैं और सैन्य बल के निर्दयी प्रयोग को ही एकमात्र समाधान मानते हैं। लेकिन बार बार होने वाले व्यापक सैन्य अभियानों के बावजूद समस्या का कोई स्थायी हल न निकल पाना यह साबित करता है कि ताकत के बल पर किसी भी जन आंदोलन को हमेशा के लिए नहीं कुचला जा सकता। इस संघर्ष का एक बेहद चिंताजनक पहलू मानवाधिकारों का निरंतर और घोर उल्लंघन है। स्थानीय और कई अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन लगातार यह आरोप लगाते रहे हैं कि पाकिस्तानी सुरक्षा बल बलूचिस्तान में व्यापक स्तर पर दमन चक्र चला रहे हैं। हजारों की संख्या में बलूच युवाओं, छात्रों, वकीलों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित तौर पर जबरन गायब कर दिया गया है। इन लापता लोगों के परिवार वाले सालों से न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं और अदालतों से लेकर सड़कों तक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन व्यवस्था उनकी पुकार सुनने को तैयार नहीं है। राज्य द्वारा की जा रही इस ज्यादती ने बलूच समाज में पाकिस्तान की केंद्र सरकार के प्रति अविश्वास की खाई को इतना चौड़ा कर दिया है कि उसे पाटना अब लगभग असंभव प्रतीत होता है। हर नई गुमशुदगी और हर नई करूर सैन्य कार्रवाई विद्रोह की आग में घी डालने का काम करती है और राज्य के खिलाफ घृणा को और गहरा करती है।

बलूचिस्तान का यह गंभीर मुद्दा अब केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला नहीं रह गया है, बल्कि इसके गहरे भू राजनीतिक और रणनीतिक निहितार्थ भी हैं। चीन और पाकिस्तान के बीच बन रहे आर्थिक गलियारों ने इस क्षेत्र के सामरिक महत्व को कई गुना बढ़ा दिया है। ग्वाटर बंदरगाह, जो अरब सागर के ठीक मुहाने पर स्थित है, चीन की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड पहल का एक प्रमुख और निर्णायक केंद्र है। चीन ने बलूचिस्तान में अरबों डॉलर का भारी निवेश किया है। लेकिन स्थानीय बलूच लोगों का दृढ़ता से यह मानना है कि इस तथाकथित विकास से उन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला है, बल्कि यह भविष्य में जनसांख्यिकीय बदलाव लाने और उनके प्राकृतिक संसाधनों को पूरी तरह से लूटने की एक नई साजिश है। यही कारण है कि विद्रोही गुट अक्सर चीनी इंजीनियरों, श्रमिकों और इस आर्थिक गलियारे से जुड़ी अहम परियोजनाओं को अपना निशाना

बनाते हैं। इन हमलों के कारण पाकिस्तान सरकार पर चीन की सुरक्षा चिंताओं को दूर करने का भारी और निरंतर दबाव रहता है। वहीं दूसरी ओर अफगानिस्तान के साथ लगने वाली ड्रूंड रेखा का पुराना विवाद इस पूरी क्षेत्रीय स्थिति को और भी अधिक जटिल बना देता है। अफगानिस्तान के साथ लगती यह लंबी और अस्थिर सीमा केवल एक लकीर नहीं है, बल्कि इसके दोनों ओर रहने वाले पशतून और बलूच समुदायों के गहरे सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध हैं। इस खुली और दुर्गम सीमा के कारण हथियारों और विद्रोहियों की आवाजाही को पूरी तरह से रोकन पाकिस्तानी सेना के लिए हमेशा एक बड़ी चुनौती बन रहती है। जब बलूच राष्ट्रवादी सीमांत क्षेत्रों में अपने नियंत्रण स्थापित करने का दावा करते हैं, तो यह सीधे तौर पर क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित करता है और अफगानिस्तान तथा पाकिस्तान के बीच पहले से मौजूद अविश्वास को और अधिक गहरा कर देता है।

वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि बलूचिस्तान की गहरी और बहुआयामी समस्या का समाधान केवल बंदूकों, सैन्य बूटों की थाप या बल प्रयोग में बिल्कुल नहीं तलाशा जा सकता। विश्व का इतिहास इस बात का गवाह है कि जिन क्षेत्रों में पहचान, संसाधन और राजनीतिक अधिकारों से जुड़े प्रश्न लंबे समय तक अनसुलझे रहते हैं, वहां राज्य को हमेशा अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। जब तक वहां के लोगों की जायज राजनीतिक और आर्थिक शिकायतों का ईमानदारी से निवारण नहीं किया जाता, तब तक कोई भी शांति बाहर से थोपी नहीं जा सकती। पाकिस्तान के नीति निर्माताओं को यह कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी कि बलूच लोगों को उनके ही घर में बेगाना और हाशिए पर रखकर एक मजबूत और एकजुट राष्ट्र का निर्माण नहीं किया जा सकता।

इस संकट के समाधान के लिए राज्य को अपनी सदियों पुरानी सैन्य और दमनकारी मानसिकता से बाहर आना होगा और एक सार्थक तथा पारदर्शी राजनीतिक संवाद की तत्काल शुरुआत करनी होगी। प्राकृतिक संसाधनों पर स्थानीय लोगों के प्रथम अधिकार को संवैधानिक मान्यता देना, विकास परियोजनाओं में उनकी सीधी और सम्मानजनक भागीदारी सुनिश्चित करना और सबसे महत्वपूर्ण बात, मानवाधिकारों के व्यापक उल्लंघन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाकर सभी लापता लोगों को निष्पक्ष न्याय दिलाना ही वह एकमात्र लोकतांत्रिक रास्ता है जो बलूचिस्तान में वास्तविक और स्थायी शांति ला सकता है। यदि पाकिस्तान के हुकूमरारों ने समय रहते अपना नीतियां नहीं बदलीं और संवाद का मार्ग नहीं अपनाया, तो बलूचिस्तान का यह रिस्ता हुआ नासूर आने वाले समय में पाकिस्तान के पूरे अस्तित्व, उसकी अर्थव्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए सबसे घातक और विनाशकारी खतरा बन सकता है।

यूपी में शिक्षकों को साधने में जुटी योगी सरकार

गांव की पगड़डियों से लेकर कस्बों की गलियों तक, उत्तर प्रदेश में %मास्टर साहब% का रुबबा किसी नेता से कम नहीं होता। बच्चों को पहाड़े रटाने वाला यही शिक्षक चुनाव के मौसम में पूरे मोहल्ले की राय बदलने की ताकत रखता है। यही वजह है कि पिछले तीन महीनों में योगी आदित्यनाथ सरकार ने शिक्षकों, शिक्षामित्रों और अनुदेशकों के लिए घोषणाओं की मानो झड़ी ही लगा दी है। कैशलेस इलाज से लेकर करोड़ों के दुर्घटना बीमा तक, हर फैसला सीधे इस बड़े वोट-बैंक को साधने की कोशिश जैसा दिख रहा है।पहले जरा आंकड़ों की जमीन पर खड़े होकर समझें कि यह तबका है किनता बड़ा। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के अंतर्गत ही करीब पांच से छह लाख नियमित शिक्षक काम कर रहे हैं। इनके साथ डेढ़ लाख के आसपास शिक्षामित्र और लगभग पच्चीस हजार अंशकालिक अनुदेशक भी इसी तंत्र का हिस्सा हैं। इसके अलावा राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षकों और स्टाफ की संख्या दो से छह लाख के बीच बैठती है। जब इनमें रिटायर हो चुके शिक्षक और इन सबके परिवार जोड़ दिए जाएं, तो यह संख्या तीस से चालीस लाख वोटों तक पहुंच जाती है। सिर्फ संख्या ही नहीं, समाज में शिक्षक की जो साख होती है, वह इस अगर को और बड़ा बना देती है। गांव का वोटर चुनाव के वक्त मास्टर साहब की बात को गंभीरता से लेता है, और चुनाव इ्यूटी से लेकर वोटर लिस्ट दुरुस्त करने तक का ज़्यादातर काम भी इन्हीं के कंधों पर टिका होता है। शायद इसीलिए कोई भी सरकार इस तबके को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहती।

अब बात करते हैं उन फैसलों की, जिनन्होंने पिछले कुछ हफ्तों में सुर्खियां बटोरीं। जुलाई 2026 में मुख्यमंत्री ने वाराणसी की धरती से %मुख्यमंत्री शिक्षक कैशलेस चिकित्सा योजना% की शुरुआत की। इस योजना के दायरे में करीब बारह से पंद्रह लाख शिक्षक, शिक्षामित्र, अनुदेशक और यहां तक कि स्कूलों में खाना बनाने वाली रसोइया बहनें भी आ गई हैं। हर परिवार को सालाना पांच लाख रुपये तक का इलाज मुफ्त मिलेगा, और



अजय कुमार

इसका प्रीमियम खुद सरकार भरेगी। यह फैसला इसलिए	पूरा खर्च प्रसरण भरेगी। यह फैसला इसलिए
---	--

भी अहम है क्योंकि लंबे समय से शिक्षक संगठन स्वास्थ्य सुरक्षा की मांग उठाते रहे हैं, खासकर कोविड के बाद जब अचानक इलाज का खर्च आम आदमी की जेब पर भारी पड़ने लगा था।इसी कड़ी में सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिलकर एक बड़ा दुर्घटना बीमा कवर भी शुरू किया है। नियमित शिक्षकों के परिवार को अब किसी हादसे की सूरत में एक करोड़ रुपये तक मिल सकते हैं, जबकि संविदा पर काम कर रहे अनुदेशकों और शिक्षामित्रों को तीस से अस्सी लाख रुपये तक का कवर दिया गया है। यह उन तबकों के लिए अलाह है, जो अब तक किसी भी तरह की सामाजिक सुरक्षा से वंचित थे।अनुदेशकों की बात करें तो उनकी कहानी थोड़ी अलग है। फरवरी 2026 में सुप्रीम कोर्ट ने उनके बेहद कम मानदेय पर नाराजगी जताई थी, जिसके बाद मई में सरकार हरकत में आई और मासिक मानदेय नौ हजार से बढ़ाकर सीधे सत्रह हजार रुपये कर दिया। यह बढोतरी एक अप्रैल 2026 से ही लागू मानी गई, यानी पीछे की तारीख से भी फायदा दिया गया। सालों से मामूली रकम में गुजारा कर रहे इन अनुदेशकों के लिए यह किसी बड़ी उम्मीद से कम नहीं था। एक और मुद्दा जो लंबे समय से शिक्षकों को परेशान कर रहा था, वह था टीईटी यानी शिक्षक पात्रता परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट ने आठवीं तक पढ़ाने वाले शिक्षकों के लिए यह परीक्षा पास करना अनिवार्य कर दिया था, जिससे बरसों से नौकरी कर रहे शिक्षकों में डर बैठा गया कि उन्हें नए और युवा अभ्यर्थियों से सीधी टक्कर लेनी पड़ेगी। इसे भांपते हुए जुलाई की शुरुआत में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन-सर्विस शिक्षकों के लिए अलग से टीईटीआई जाएं, ताकि वे बिना किसी अतिरिक्त दबाव के अपनी पात्रता साबित कर सकें। साथ ही जुलाई की यूपीटीईटी परीक्षा में बैठने वाले कार्यरत शिक्षकों को विशेष अवकाश भी दिया गया। इसके

अलावा शहरी इलाकों के स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी को देखते हुए दस हजार से ज्यादा नए पदों पर भर्ती का खाका भी नवगठित उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजा जा चुका है।लेकिन सिक्रे का दूसरा पहलू भी उतना ही असरदार है। पुरानी पेंशन योजना यानी ओपीएस की मांग सालों से शिक्षक संगठनों की सबसे बड़ी मांग बनी हुई है, और सरकार अब तक इसे वित्तीय बोझ बताकर टालती रही है। चुनाव जैसे-जैसे नजदीक आते हैं, विपक्ष इस मुद्दे को हवा देने से नहीं चुकता। दूसरी बड़ी टीस शिक्षामित्रों की है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने सवा लाख से ज्यादा शिक्षामित्रों का सहायक शिक्षक पद पर समायोजन रद्द कर दिया था, और तब से यह मामला जस का तस अटक पड़ा है। मानदेय में मामूली सुधार तो हुए हैं, पर समान काम समान वेतन और पूर्ण नियमितीकरण की मांग आज भी अधूरी है, और यह गुस्सा वक्त-वक्त पर सड़कों पर आंदोलन की शकल ले लेता है।

इसी साल जून-जुलाई में लागू हुई त्रि-स्तरीय तबादला और समायोजन नीति ने भी शिक्षकों को उत्तन्न में डाल दिया। इसके अलावा स्कूलों में अनिवार्य की गई डिजिटल हाजिरी को लेकर भी प्रदेशभर में तीखा विरोध देखने को मिला। शिक्षकों का कहना है कि दूर-दराज के गांवों में जहां नेटवर्क ठीक से पकड़ता ही नहीं, वहां रोज ऑनलाइन हाजिरी लगाना व्यावहारिक तौर पर मुश्किल है। कुल मिलाकर देखा जाए तो कैशलेस इलाज, मोटा दुर्घटना बीमा और अनुदेशकों के मानदेय जैसी सोगाते सरकार के प्रति शिक्षकों की नाराजगी को काफी हद तक कम करने वाली साबित हो सकती है। अलग टीईटी का वादा भी इस तबके में राहत का माहौल बना गया है। पर पुरानी पेंशन और शिक्षामित्रों के नियमितीकरण जैसे बुनियादी सवाल अब भी जवाब पार रहे हैं। आने वाले समय में यही देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये तमाम मरहम शिक्षकों के पुराने जख्मों को पूरी तरह भर पाते हैं, या फिर चुनाव नजदीक आते ही यह असंतोष एक बार फिर सतह पर आ जाता है।

धरती की कोख उजाड़कर कितने दिन चमकेगा सोने का वैभव?

सोने का भाव जितनी ऊंचाई छू रहा है, धरती उतनी ही गहराई में धंस रही है। वित्तीय बाजार इसे सुरक्षित निवेश का स्वर्णकाल मान रहे हैं, जबकि प्रकृति इसे अपने अस्तित्व का काला अध्याय। तिजोरियां भर रही हैं, लेकिन नदियां विष से, जंगल वीरानी से और आदिवासी अंचल भय से भर रहे हैं। कभी वैभव, विश्वास और स्थिरता का प्रतीक रही यह पीली धातु आज पर्यावरणीय संक्रा, संगठित अपराध और वैश्विक अस्थिरता की नई मुद्रा बन चुकी है। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि बाजार सोने का मूल्य चुकाता है, उसकी पर्यावरणीय कीमत नहीं। हर बढ़ता भाव किसी जंगल की हरियाली, किसी नदी की निर्मलता और किसी समुदाय के भविष्य को गिरवी रखकर हासिल हो रहा है।

उन्नीसवीं सदी की गोल्ड रश अवसरों की कहानी थी, इक्कीसवीं सदी की यह स्वर्ण-दौड़ अस्तित्व का संकट है। सोने की ऊंची कीमतों ने लघु स्वर्ण खनन (आर्टिजनल एंड स्मॉल-स्केल गोल्ड माइनिंग) को अभूतपूर्व रफ्तार दे दी है। छोटे और अवैध खनिक अब केवल धरती की छाती नहीं चीर रहे, पूरी आपूर्ति श्रृंखला पर शिकंजा कस रहे हैं। घाना, अमेज़न, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कई इलाकों में जंगल ऐसे उजाड़े जा रहे हैं, मानो वे धरती के फेफड़े हों, लालच के रास्ते की बाधा हों। खनन अब उद्योग नहीं, प्रकृति पर संगठित उकैती है। जहां कभी पक्षियों का कलरव था, वहां अब मशीनों का शोर और विस्फोट हैं। इस विनाश की सबसे भयावह तस्वीर नदियों में दिखाई देती है। सोना निकालने की सबसे सस्ती तकनीक—पारा (मरकरी) और सायनाइड—आज भविष्य की सबसे महंगी कीमत वसूल रही है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनएपी) के अनुसार, दुनिया में मरकरी प्रदूषण का लगभग 37 प्रतिशत हिस्सा केवल आर्टिजनल एंड स्मॉल-स्केल गोल्ड माइनिंग (एसजीएम) से आता है। हर वर्ष 800 टन से अधिक पारा हवा और जल स्रोतों में घुलकर मछलियों के जरिए पूरी खाद्य श्रृंखला में फैलता है तथा बच्चों के मस्तिष्क विकार पर स्थायी चोट करता है। घाना इसका सबसे दर्दनाक उदाहरण है, जहां लगभग 60 प्रतिशत जल स्रोत दूषित हो चुके हैं और अनेक नदियां पीने योग्य नहीं रहीं। यह केवल जल प्रदूषण नहीं, मानव सभ्यता की जीवनरेखा में घोला जा रहा धीमा जहर है।

यह केवल पर्यावरण का नहीं, संगठित अपराध के फैलते साम्राज्य का भी वृतांत है। अमेज़न के जंगलों में स्वर्ण खनन अब ड्रा कार्टेलों और अपराधी गिरोहों का नया अड्डा बन चुका है। अनेक क्षेत्रों में इसका मुनाफा कोकीन के कारोबार से भी अधिक माना जा रहा है। चीनी अपराधी नेटवर्क -फ्लाइंग मनी- के जरिए सोने

के लेन-देन में कर रहे हैं। नतीजा यह है कि वहां केवल जंगल ही नहीं उजड़ रहे, कानून का राज भी मिटता जा रहा है। जैव विविधता सिमट रही है, आदिवासी अपनी पुरतैनी जमीन से बेदखल हो रहे हैं और हिंसा जीवन की सामान्य सच्चाई बनती जा रही है। बाज़ील के मुंडुरुकु आदिवासी क्षेत्र में खनन थमने के बाद भी स्वास्थ्य संकट कायम है। संदेश साफ है—खदानें बंद हो सकती हैं, लेकिन प्रकृति और समाज पर पड़े उनके घाव पीढ़ियों तक नहीं भरते।

यह मानना भूल होगी कि यह संकट केवल अमेज़न या अफ्रीका तक सीमित है। भारत में कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में अवैध स्वर्ण खनन तेजी से समानांतर अर्थव्यवस्था का रूप ले रहा है। सरकारी राजस्व लूट रहा है, वन सिकुड़ जा रहे हैं और नदियां जहर निगल रही हैं। यहां भी पारे का अंधाधुंध इस्तेमाल मछलियों, खेती और ग्रामीण स्वास्थ्य पर भारी पड़ रहा है। वैश्विक बाजार में सोने की कीमत चढ़ते ही स्थानीय जंगलों पर दबाव कई गुना बढ़ जाता है। वैश्वीकरण का यही कठोर सच है कि लंदन और न्यूयॉर्क के निवेशकों का मुनाफा, झारखंड और छत्तीसगढ़ के जंगलों की कीमत पर लिखा जा रहा है।

सबसे बड़ा भ्रम यही है कि सोना आज भी केवल आपूषण या निवेश है। सच यह है कि वह अब भू-राजनीति, प्रतिबंधों से बच निकलने, भ्रष्टाचार और राजनीतिक वित्तपोषण का भी सशक्त माध्यम बन चुका है। किफसित देशों के बाजारों तक पहुंचने वाला सोना अपने पीछे छूटे विनाश के निशान साथ नहीं ले जाता। शायद ही किसी उपभोक्ता को पता हो कि उसकी उंगली में चमकती एक साधारण शादी की अंगूठी के पीछे लगभग 20 टन जहरीला खनन अपशिष्ट छिपा है। बाजार धातु की शुद्धता तो परखता है, लेकिन उसके उत्पादन की नैतिकता पर चुपि साध लेता है। आधुनिक अर्थव्यवस्था की यही सबसे बड़ी विडंबना है—मुनाफा कुछ हाथों में सिमटता है, जबकि उसकी पर्यावरणीय कीमत पूरी पृथ्वी चुकाती है। समाधान केवल अवैध खनन पर छापेमारी में नहीं, बल्कि वैश्विक जवाबदेही में है। पारा-मूक्त तकनीकों को बढ़ावा देना होगा, छोटे खनिकों के लिए वैकल्पिक आजीविका सुनिश्चित करनी होगी और पूरी आपूर्ति श्रृंखला को पारदर्शी बनाना होगा, ताकि बाजार तक पहुंचने वाले हर ग्राम सोने की पूरी यात्रा दर्ज रहे। जब तक दुनिया केवल हॉलमार्क देखेगी और उसके पर्यावरणीय पदचिह्न नहीं पूछेगी, तब तक यह संकट थमेगा नहीं। विकास का अर्थ प्रकृति की कीमत पर समृद्धि नहीं, बल्कि संसाधनों और संवेदनाओं के बीच संतुलन है।

cm^yk +

cm^yk +

सभी प्रमुख बाँधों, जलाशयों, रपटों एवं संवेदनशील स्थलों पर चेतावनी सूचना-पट्ट अनिवार्य रूप से लगाएं : मण्डलायुक्त

■ अधिकारी अपनेक्षेत्रों के अन्त्येष्टि स्थलों का निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें



झाँसी जयूस। मण्डलायुक्त बिमल कुमार दुबे की अध्यक्षता में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक आयुक्त सभागार में आयोजित की गयी। उन्होंने जहाँजानसामान्य का अधिक आवागमन होने वाले सड़क सार्वजनिक रास्तों एवं सड़क किनारे गहरे गड्ढे होने पर वाहन गिरने की घटनाएं, जनहानि एवं बच्चों के

रपटें वाले क्षेत्रों की बैरिकेडिंग कर आमजन की आवाजाही को नियंत्रित करने हेतु निर्देशित किया। सिंचाई विभाग, जल निगम, पंचायत, लोक निर्माण विभाग, लघु सिंचाई, पुलिस, राजस्व विभाग नियमित निगरानी करें और संवेदनशील स्थलों पर आवश्यकतानुसार सुरक्षा कर्मियों को तैनाती सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने निर्देश दिए कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाया जाए। ग्राम पंचायतों, नगर निकायों, विद्यालयों तथा अन्य माध्यमों से लोगों को बांधों, नदियों एवं गहरे जलाशयों में स्नान, सेल्फी लेने अथवा अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों से बचने के लिए जागरूक किया जाए। उन्होंने कहा कि जनसहयोग और प्रशासनिक सतर्कता के माध्यम से ही डूबने की घटनाओं पर प्रभावी नियंत्रण संभव है। किसी भी आपात स्थिति में

व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। मण्डलायुक्त ने टहरीली क्षेत्र में तिरपाल लगाकर अंतिम संस्कार करने वाली घटना पर कड़ी नाराजगी व्यक्त करते हुए डीडी पंचायत को निर्देश दिए कि अन्त्येष्टि स्थलों, अस्पतालों एवं विद्यालयों के रास्तों को सुगम बनायें, जिससे आमजन व विद्यालय जाने वाले बच्चों को आने जाने में परेशानी न हो। उन्होंने संबंधित विभागों को आपसी समन्वय के साथ सभी आवश्यक सुरक्षा उपाय समयबद्ध रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और सम्बन्धित अधिकारी अपने-अपने क्षेत्रों के अन्त्येष्टि स्थलों का नियमित निरीक्षण कर आवश्यक व्यवस्थाएँ सुनिश्चित करें। मण्डलायुक्त ने कहा कि तहसील स्तर पर किसान सम्मान निधि के लम्बित आवेदनों का निस्तारण अभियान के साथ पूर्ण करायें। उन्होंने कहा कि श्रम विभाग के पोर्टल पर श्रमिकों का अधिक से

कार्य, गर्भवती महिलाओं व छोटे बच्चों को पोषाहार वितरण, बाल वाटिका, मुख्यमंत्री कन्या सुगमला योजना, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, अभ्युदय योजना, किसान सम्मान निधि, स्वच्छ भारत मिशन, आंगनबाड़ी केन्द्रों का निर्माण, निराश्रित गौवंश आश्रय स्थल सहित निर्माणाधीन कार्यों में प्रगति बढ़ाने के निर्देश दिये। बैठक में संयुक्त विकास आयुक्त सुरेश चन्द्र केसरवानी, अपर नगर आयुक्त रैली गुप्ता, संयुक्त निदेशक शिक्षा आर के वर्मा, उप निदेशक अर्थ एवं संख्या एस.एन.त्रिपाठी, अपर निदेशक पशुपालन ए.केसागर, उपायुक्त खाद्य विनय कुमार, उप निदेशक पंचायती राज अजय आनन्द सरोज, उप निदेशक महिला कल्याण श्रवण गुप्ता, उप निदेशक दिव्यांगजन सशक्तिकरण शिव सिंह, उप निदेशक समाज कल्याण इन्द्रा सिंह, अधीक्षण अभियंता लोक निर्माण विभाग संजीव कुमार सहित अन्य सम्बन्धित मण्डलीय अधिकारीगण उपस्थित रहे।

न्यूज ब्रीफ

श्री लाला हरदौल से की अच्छी बरसात के लिए प्रार्थना



झाँसी जयूस। अन्दर सैंयर गेट स्थित श्री लाला हरदौल कुशवाहा समाज मन्दिर (श्री लाला हरदौल कुशवाहा समारं वैलफेयर सोसायटी) के तत्वावधान में प्रत्येक वर्ष की भाँति रविवार को आषाण माह की पूजा अर्चना विधिवत पुजारी कैलाश चन्द कुशवाहा द्वारा की गई। जिसमें समिति के सभी सदस्य व समाज के पुरुषों, महिलाओं के साथ ही बच्चों ने भी बट-चट कर भाग लिया। श्रद्धालुओं /समाज बन्धुओं ने प्रति वर्ष की भाँति उन्होंने आस्था और विश्वास के साथ श्री लाला हरदौल महाराज से अच्छी बारिश के लिए प्रार्थना की है। इस अवसर पर अध्यक्ष महेश चन्द्र, मनोज, जानकी प्रसाद, प्रेम नारायण, गौरीशंकर कुशवाहा ,हरवंश, हरी प्रकाश, शोभा कुशवाहा, गीता, फूलवती, शकुन्तला,मिथिला देवी,कुसुम देवी आदि उपस्थित रहे।

स्वास्थ्य परीक्षण शिविर मेंकी गई जाँच



झाँसी जयूस। श्रीभोले नाथ खाती बाबा एवं साईं सेवा समिति द्वारा न्यू लाइफ क्लीनिक उन्नाव गेट बाहर पत्थर की टाल पर नि.शुल्क नेत्र रोग. स्त्री रोग, बी. पी सुगर जर्नल फिजिशियन परीक्षण शिविर लगाया गया। शिविर मेंमरीजों के स्वास्थ्य की जाँच हुई। डॉक्टरों ने मरीजों का रक्तचाप, सुगर आँखें स्त्री रोग व सामान्य रोगों की जाँच की गई। जाँच के बाद आवश्यकतानुसार दवाइयों वितरित की गई। बीमारियों से बचाव और खान-पान के बारे में जरूरी सलाह दी गई। 325 नेत्र रोगियों की जाँच व 32 लोगों के मोतिया बिन्दु ऑपरेशन की आगामी तिथि दी गई। 175 महिलाओं की जाँच व नि.शुल्क दवा दी गई। 250 लोगों व सुगर की जाँच की गई। 50 लोगों की फिजिशियन सर्जन द्वारा जांच व दवा दी गई। शिविर में उपस्थित रहे डॉ.जी एस अर्गल नेत्र रोग विशेषज्ञ, डॉ. श्रीमती रुषा अर्गल स्त्री रोग विशेषज्ञ,डॉ. मनसून इलाही फिजिशियन सर्जन, डॉ. सविहा इलाही ने लोगों का इलाज किया।

इस अवसर पर रहबर इलाई, शरीफ मकरानी, जहीर भाई, मतलूब, इंद्रपाल सिंह, साइ इलाही, अविनाश सिंह, संजीव बुन्देला, अकिंत श्रीवास्तव, अंशुल वर्मा, रेनु, सुधीर कुमार, आराधना, निविशा, दिव्याश, साक्षी, तनु साहिबा, राकेश आदि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन समाज सेवी अज्जू मेहरोलिया ने किया। आभार व्यक्त डॉ संजय गौतम ने किया।

कांग्रेस है तो विश्वास है के नारे के साथ प्रबुद्धजन के बीच पहुँचने का आह्वान



झाँसी जयूस। प्रबुद्ध वर्ग के बीच कांग्रेस है तो विश्वास है के नारे के साथ पहुँचने की मुहिम तैयार की गई है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमटी शिक्षक प्रकोष्ठ की प्रदेश महासचिव सायमा नेमान बताती हैं कि पार्टी का लम्बा इतिहास, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण और जनकल्याणकारी नीतियों का रहा है। इसमें देश का विकास और जन अधिकारों की रक्षा सम्मिलित है। उन्होंने प्रभार क्षेत्र में पदाधिकारियों से इस मुहिम में सक्रिय होने का आह्वान किया। इस दौरान मोहम्मद शाहिद, प्रभुदयाल अहिरवार, सुलभ राय, आरिफ सलीम, मुमताज अहमद, किशोर कुमार, फिरोज खान आदि ने विचार व्यक्त किए।

गौ वंश केगोबर व मूत्र के उपयोग से जहर मुक्त प्राकृतिक खेती पर दिया जोर

भूसे, पेयजल व जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें:अध्यक्ष गौ-सेवा आयोग



झाँसी जयूस। गौसेवा आयोग अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्ता की अध्यक्षता में कलैक्टेट नवीन सभागार में पशुपालन विभाग की जिला स्तरीय अनुश्रवण, मूल्यांकन एवं समीक्षा समिति की बैठक

आयोजित की गई। बैठक में जनपद के विभिन्न गोआश्रय स्थलों में संरक्षित निराश्रित गोवंशों केसंरक्षण, भरण-पोषण, चिकित्सा एवं मूलभूत व्यवस्थाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। अध्यक्ष गौ

सेवा आयोग ने गौवंशों के समुचित रख-रखाव को शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में बताते हुए संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक व्यवस्थाएँ समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित करने के निर्देश

दिए। अध्यक्ष गौ सेवा आयोग श्याम बिहारी गुप्ता ने कहा कि समस्त जनप्रतिनिधियों से एक-एक गोशाला गोद लेने हेतु आग्रह किया जाए एवं उनकी निधि के माध्यम से उस गौ आश्रय स्थल में आधारभूत संरचना से आच्छादित करने हेतु निवेदन किया जाए। उन्होंने बताया कि उनके द्वारा भी ग्राम पलींदा में गौआश्रय स्थल को गोद लिया गया है। उन्होंने कहा कि वर्तमान वर्षा ऋतु को देखते हुए किसी भी गौ आश्रय स्थल में जलभराव की स्थिति नहीं होनी चाहिए। सभी संबंधित अधिकारी नियमित निरीक्षण कर जल निकासी की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करें, ताकि गोवंशों को किसी प्रकार की अस्वुिधा या बीमारी का सामना न करना पड़े।

युवा श्रद्धालुओं व विशेष सहयोगियों का किया सम्मान

भगवान जगन्नाथ सेवा समिति की बैठक में मंदिर को भव्य स्वरूप देने का लिया संकल्प



झाँसी जयूस। जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ सेवा समिति की बैठक हुई। बैठक की अध्यक्षता संजय नौराई ने की। भव्य रथयात्रा में विशेष सहयोग करने वाले युवा श्रद्धालुओं एवं सहयोगियों का

सम्मान किया गया। दुर्गा उत्सव समिति के पीयूष रावत ने कहा कि शास्त्रों में कहा गया है कि प्राचीन मंदिर के जीर्णोद्धार में आर्थिक सहयोग व दान करने से व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि में वृद्धि

होती है। पुण्य फल की प्राप्ति होती हैं। पूर्वज तथा देवता प्रसन्न होते हैं। खुशहाली का आशीर्वाद देते हैं। उन्होंने कहा कि सभी श्रद्धालु उत्साह से सहयोग करें। इस अवसर पर अध्यक्ष संजय नौराई, पुरुषोत्तम स्वामी ,मुकेश अग्रवाल, डॉ.संजय त्रिपाठी, गोकुल दुबे, अनिल नागरिया, दुष्यंत चतुर्वेदी, मनीष

तिवारी, महेश सराफ, मैथिली मुद्गिल, महेंद्र भंडारी, जयदीप खरे, सखेंद्र पुरी, पवन गुप्ता, प्रभात शर्मा, विनोद हयारण, विनय आनंद, शिवा नौराई, ध्रुव नौराई आदि उपस्थित रहे।

शिवाजी नगर प्रवास पर मैराथन बैठकों के साथ जिलाध्यक्ष ने अनुसूचित समाज के वरिष्ठजनों को किया सम्मानित

कार्यक्रम में धानुक, बरार, वंशकार समाज सहित प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को किया सम्मानित



झाँसी जयूस। भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक प्रवास अभियान केमहानगर जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने शिवाजी नगर मंडल का एक दिवसीय प्रवास किया। इस प्रवास का मुख्य उद्देश्य डिजिटल लर्निंग प्रोग्राम के जरिए प्रत्येक बूथ पर 25 कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाना और केंद्र व राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं को जन-जन तक पहुंचाना है। प्रवास के तीसरे दिन संगठन को बूथ स्तर

तक मजबूत करने के लिए बैठकों और जनसंपर्क शुरू किया। डिजिटल सशक्तिकरण और रणनीतिक बैठकें जिलाध्यक्ष सुधीर सिंह ने प्रवास के दौरान विभिन्न संगठनात्मक स्तरों पर मैराथन बैठकें कीं। इन बैठकों को मुख्य रूप सेइन श्रेणियों में विभाजित किया गया बूथ स्तरीय संवाद कार्यकर्ताओं को डिजिटल रूप से सक्रिय करने के लिए बूथ समिति और पन्ना प्रमुखों के साथ संगठनात्मक चर्चा की गई। साथ ही

चौधरी नंबर 33 में शक्ति केंद्र के प्रवासियों और संयोजकों की बैठक लेकर जिम्मेदारियां तय की गईं। स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा, वार्ड नंबर 18 में मंडल के पार्षदों, पूर्व पार्षदों और पार्षद प्रत्याशियों के साथ बैठक कर स्थानीय विकास और जनसमस्याओं पर मंथन हुआ। वार्ड नंबर 27 में पदाधिकारियों व मोर्चा अध्यक्षों के साथ विमर्शमंडल के पदाधिकारियों, मोर्चा अध्यक्षों, महामंत्रियों, संयोजकों, सह-संयोजकों और महिला पदाधिकारियों के साथ बैठक कर आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार की गई। वार्ड नंबर 54 में मंडल में निवास करने वाले पूर्व जिला व मंडल पदाधिकारियों, पुरातन एवं वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और विचार परिवार के सदस्यों के साथ विशेष बैठक कर उनका मार्गदर्शन लिया गया। चाय पर चर्चाओं

जानसंपर्क औपचारिक बैठकों के अलावा जिलाध्यक्ष ने जमीनी जुड़ाव को मजबूत करने के लिए मंडल पदाधिकारियों के साथ बैठक की और वार्ड नंबर 2 में बूथ अध्यक्षों के निवास पर चाय पर चर्चा की। उन्होंने स्थानीय पाकों का भ्रमण कर आम नागरिकों और उनके परिजनों से भी सीधा संवाद स्थापित किया। इसके साथ ही क्षेत्र के मठ-मंदिरों में दर्शन मै काली माता के मंदिर के दर्शन कर गुरुजनों का आशीर्वाद लिया। प्रवास के अंतिम चरण में वार्ड नंबर 4 खुशीपुरा मंडल प्रभारी, सह प्रभारी के साथ समीक्षा बैठक आयोजित हुई। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में रविवार को एक सम्मान समारोह का आयोजन किया। जिसमेंअनुसूचित मोर्चा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में धानुक, बरार, वंशकार समाज सहित प्रबुद्ध वर्ग के लोगों को सम्मानित किया। समारोह में समाज के लोगों ने बड़-चढ़कर हिस्सा लिया और अपनी एकजुटता प्रदर्शित की। समारोह के

दौरान समाज के विभिन्न वक्ताओं ने धानुक, बरार और वंशकार समाज की वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डाला। वक्ताओं ने मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष के समक्ष अपनी बात रखते हुए आगामी समय में समाज को उचित राजनैतिक प्रतिनिधित्व और भागीदारी दिलाए जाने की मांग रखी।संजीव अग्रवाल एवं कपिल विरसैनिया , बालकिशन जिला पंचायत सदस्य चिरगांव समारोह में संजीव अग्रवाल ,कपिल विरसैनिया , बालकिशन जिला पंचायत सदस्य चिरगाँव, बबोना के पूर्व ब्लॉक प्रमुख कल्याण सिंह बरार, ललितपुर से आए समाज चिंतक खुशाल बरार, आशाराम धानुक, नरेंद्र धानुक, रोहित - मऊरानीपुर, मिलन वंशकार -ग्रधान, भगवान दास, परशुराम - नरूआसागर, कमल मुखिया, अमान रायकर, रतन लाल पासवान, किरन वर्मा, मनीष, नारायण दास, अमित पासवान, कन्हैया, बलवीर, रवि,

स्वाधिकारी, मुद्रक एवं प्रकाशक नाथूराम कुशवाहा द्वारा जनता यूनियन प्रेस, शिव परिवार कालोनी, उन्नाव गेट बाहर झाँसी से मुद्रित एवं प्रकाशित। संपादक - नाथूराम कुशवाहा*

फोन नं. 0510-2331158 आरएनआई नं. यूपीएचआईएन/2007/22191 समस्त विवादों का निपटारा झाँसी न्यायालय के अधीन होगा। *पी.आर.बी. एक्ट के तहत समाचार चयन के लिए उत्तरदायी